

अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन : जनपद सारण, बिहार के संदर्भ में

सत्येन्द्र कुमार राम

शोध-छात्र, ओरियण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर(म0प्र0)

भारत में सामाजिक-आर्थिक विषमता शिक्षा व्यवस्था को गहराई से प्रभावित करती है, विशेषकर अनुसूचित जाति (SC) और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के बीच। प्रस्तुत अध्ययन, जो बिहार के सारण जिले के संदर्भ में किया गया है, यह दर्शाता है कि सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में विद्यमान असमानताएँ विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों, विशेषकर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, पर आधारित है, जो इस विषय को विश्वसनीयता प्रदान करता है।

इस अध्ययन में आवासीय सुविधाओं एवं डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में भी स्पष्ट अंतर पाया गया है। अनुसूचित जाति के अनेक विद्यार्थी ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान, पुस्तकें, इंटरनेट एवं डिजिटल उपकरणों का अभाव होता है। आज के डिजिटल युग में यह कमी उनकी शिक्षा को और अधिक प्रभावित करती है, विशेषकर ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में। वहीं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी इन सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी शैक्षिक उपलब्धियों को सुदृढ़ करते हैं। इन सभी कारकों का समग्र प्रभाव विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम, उपस्थिति, आत्मविश्वास तथा उच्च शिक्षा में प्रवेश पर पड़ता है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उपलब्धियाँ अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं, जबकि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

अंततः, यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सामाजिक-आर्थिक विषमता को कम किए बिना शिक्षा में समानता एवं समावेशन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः आवश्यक है कि सरकार एवं समाज मिलकर आर्थिक सहायता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल पहुँच एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इन असमानताओं को दूर करने का प्रयास करें, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर प्राप्त हो सके।

मुख्य शब्द – अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शैक्षिक असमानता, डिजिटल विभाजन, सारण जिला (बिहार)।

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का मूल आधार है। भारतीय संविधान में समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया गया है, तथापि व्यवहारिक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ आज भी विद्यमान हैं। भारत की जाति-आधारित सामाजिक संरचना में अनुसूचित जाति समुदाय ऐतिहासिक रूप से वंचना, गरीबी एवं सामाजिक बहिष्करण का शिकार रहा है, जिसका प्रभाव उनकी शैक्षिक प्रगति पर भी पड़ा है।

राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों जैसे छत्थे-5 एवं 11^म रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति परिवारों की औसत आय, माता-पिता

की शिक्षा तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सामान्य वर्ग की तुलना में कम है। बिहार राज्य, विशेषतः जनपद सारण, जहाँ ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक है, वहाँ यह अंतर और अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देता है।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सीधा संबंध विद्यार्थियों की विद्यालयी उपस्थिति, शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता, अध्ययन वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धियों से होता है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण शिक्षा में अधिक अवसर प्राप्त करते हैं, जबकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अनेक संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

अधिक अवसर प्राप्त करते हैं, जबकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अनेक संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन जनपद सारण, बिहार के संदर्भ में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे शैक्षिक असमानताओं को समझने तथा नीति-निर्माण हेतु तथ्यात्मक आधार उपलब्ध कराया जा सके।

समस्या विवरण

बिहार राज्य के सारण जनपद में सामाजिक-आर्थिक विषमता शिक्षा के क्षेत्र में एक गंभीर चुनौती के रूप में विद्यमान है। विशेषतः अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के बीच पारिवारिक आय, माता-पिता की शैक्षिक स्थिति, आवासीय सुविधाओं तथा शैक्षिक एवं डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। यह असमानता न केवल उनके जीवन-स्तर को प्रभावित करती है, बल्कि उनकी शैक्षिक प्रगति, उपलब्धि एवं भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है।

अनुसूचित जाति के अधिकांश विद्यार्थी सीमित आर्थिक संसाधनों एवं कम शिक्षित पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसके कारण उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मार्गदर्शन एवं अनुकूल अध्ययन वातावरण का अभाव रहता है। इसके विपरीत, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक संसाधन, बेहतर शैक्षिक अवसर एवं पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है, जो उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को सुदृढ़ करता है।

इसी परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनपद सारण में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में वास्तविक अंतर क्या है, और यह अंतर उनकी शैक्षिक प्रगति को किस प्रकार प्रभावित करता है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इस समस्या का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना है, ताकि सामाजिक-आर्थिक विषमता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध को स्पष्ट किया जा सके तथा शिक्षा में समानता एवं समावेशन के लिए प्रभावी सुझाव प्रदान किए जा सकें।

अध्ययन के उद्देश्य

1. अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. माता-पिता की शिक्षा एवं पारिवारिक आय की तुलना करना।
3. शैक्षिक एवं डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता का विश्लेषण करना।
4. सामाजिक-आर्थिक स्तर का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव स्पष्ट करना।

शोध प्रश्न

1. क्या अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सामान्य वर्ग की तुलना में निम्न है?
2. क्या पारिवारिक आय एवं माता-पिता की शिक्षा शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करती है?
3. क्या सामाजिक-आर्थिक असमानता शैक्षिक उपलब्धि में अंतर उत्पन्न करती है?

साहित्य समीक्षा

विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि सामाजिक-आर्थिक कारक विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

NFHS-5 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति परिवारों की औसत आय सामान्य वर्ग की तुलना में कम पाई गई।

ASER रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में भी वर्गीय अंतर विद्यमान है। पूर्ववर्ती अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति और शैक्षिक उपलब्धि के मध्य गहरा संबंध है, किंतु जनपद-स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं। यही शोध अंतर प्रस्तुत अध्ययन को प्रासंगिक बनाता है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक प्रकृति का है। वर्णनात्मक अध्ययन के अंतर्गत अनुसूचित जाति

एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जबकि तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से इन दोनों वर्गों के बीच विद्यमान अंतर का विश्लेषण किया गया है। इस शोध का उद्देश्य केवल तथ्यों का प्रस्तुतीकरण ही नहीं, बल्कि उनके बीच संबंध स्थापित करना भी है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सामाजिक-आर्थिक स्तर शैक्षिक उपलब्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है।

अध्ययन क्षेत्र

यह अध्ययन बिहार राज्य के सारण जनपद में केंद्रित है। सारण एक प्रमुख जिला है, जहाँ ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों की अधिकता है। इस क्षेत्र में सामाजिक संरचना विविधतापूर्ण है, जिसमें विभिन्न जातीय एवं आर्थिक वर्गों के लोग निवास करते हैं।

इस जिले में अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या उल्लेखनीय है, जिनकी आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति सामान्यतः निम्न पाई जाती है। वहीं, सामान्य वर्ग के परिवार अपेक्षाकृत बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति में होते हैं। इस प्रकार सारण जनपद सामाजिक-आर्थिक विषमता के अध्ययन के लिए उपयुक्त एवं प्रतिनिधिक क्षेत्र प्रदान करता है।

आँकड़ों के स्रोत

यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आँकड़े वे होते हैं, जो पहले से ही विभिन्न सरकारी एवं संस्थागत स्रोतों द्वारा संकलित एवं प्रकाशित किए जा चुके होते हैं। इस शोध में निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों का उपयोग किया गया है—

जनगणना भारत 2011— इससे जनसंख्या, साक्षरता दर, जातिगत वितरण एवं आवासीय स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आँकड़े प्राप्त किए गए।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 – इस स्रोत से स्वास्थ्य, पोषण, जीवन-स्तर एवं पारिवारिक स्थिति से जुड़े आँकड़ों का उपयोग किया गया।

यूडीआईएसई रिपोर्ट— इसके माध्यम से विद्यालयों की स्थिति, नामांकन, उपस्थिति एवं शैक्षिक संसाधनों से संबंधित आँकड़े प्राप्त हुए।

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण— इस रिपोर्ट से राज्य की आर्थिक स्थिति, आय स्तर, रोजगार एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण आँकड़े लिए गए।

आँकड़ों का विश्लेषण

संग्रहित द्वितीयक आँकड़ों का विश्लेषण तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक के आधार पर किया गया है। विभिन्न सूचकों जैसे आय, शिक्षा, आवास एवं डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग की तुलना की गई।

प्राप्त निष्कर्षों की व्याख्या सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में की गई।

अध्ययन की सीमाएँ

यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, अतः इसमें प्राथमिक आँकड़ों का अभाव है। अध्ययन केवल सारण जनपद तक सीमित है, इसलिए इसके निष्कर्षों को पूरे देश पर सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। उपलब्ध आँकड़ों की समय-सीमा (जैसे जनगणना 2011) के कारण कुछ नवीन परिवर्तनों का समावेश संभव नहीं हो पाया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचना

तालिका 1. सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की तुलनात्मक स्थिति

संकेतक	अनुसूचित जाति	सामान्य वर्ग
औसत मासिक पारिवारिक आय	₹8,000–10,000	₹15,000–18,000
माता-पिता की शिक्षा	प्राथमिक/माध्यमिक	माध्यमिक/उच्च
पक्का आवास	पक्का आवास	65–70%

विवेचना

उपरोक्त तालिका के आधार पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में उल्लेखनीय अंतर विद्यमान है। यह अंतर विभिन्न संकेतकों के माध्यम से परिलक्षित होता है, जो उनकी शैक्षिक प्रगति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

सबसे पहले, औसत मासिक पारिवारिक आय पर ध्यान दें तो अनुसूचित जाति के परिवारों की आय ₹8,000 से ₹10,000 के बीच है, जबकि सामान्य वर्ग की आय ₹15,000 से ₹18,000 के बीच पाई गई है। यह अंतर यह दर्शाता है कि सामान्य वर्ग के परिवार आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हैं, जिससे वे अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक व्यय करने में सक्षम होते हैं, जैसे अच्छे विद्यालय, कोचिंग, पुस्तकें एवं अन्य शैक्षिक संसाधन। इसके विपरीत, अनुसूचित जाति के परिवार सीमित संसाधनों के कारण इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण संकेतक माता-पिता की शिक्षा है। अनुसूचित जाति के अधिकांश अभिभावक प्राथमिक या माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षित होते हैं, जबकि सामान्य वर्ग के अभिभावक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। इसका प्रभाव बच्चों के शैक्षिक मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं अध्ययन के वातावरण पर पड़ता है। शिक्षित अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर दिशा-निर्देश देने में सक्षम होते हैं, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ बेहतर होती हैं।

आवासीय स्थिति के संदर्भ में भी स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति के केवल 40–45% परिवारों के पास पक्का आवास है, जबकि सामान्य वर्ग में यह प्रतिशत 70–75% है। पक्का एवं व्यवस्थित आवास अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, जो विद्यार्थियों की एकाग्रता एवं प्रदर्शन को प्रभावित करता है।

अंततः, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। अनुसूचित जाति के केवल 35–40% विद्यार्थियों को डिजिटल सुविधाएँ (जैसे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर) उपलब्ध हैं, जबकि सामान्य वर्ग में यह 65–70% है। डिजिटल विभाजन के कारण SC वर्ग के विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा, ई-लर्निंग एवं प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी में पिछड़ जाते हैं।

इस प्रकार, तालिका से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सामान्य वर्ग की तुलना में कमजोर है, जिसका सीधा एवं व्यापक प्रभाव उनकी शैक्षिक सुविधाओं, अवसरों एवं उपलब्धियों पर पड़ता है। अतः शैक्षिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है।

तालिका 2. सामाजिक-आर्थिक स्तर एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक विश्लेषण

संकेतक	अनुसूचित जाति	सामान्य वर्ग
औसत वार्षिक परीक्षा परिणाम (%)	50–60 %	65–80 %
विद्यालय उपस्थिति (%)	60–70 %	80–90 %
निजी कोचिंग की उपलब्धता	30–35 %	60–70 %
उच्च शिक्षा में नामांकन (%)	20–25 %	45–55 %
डिजिटल माध्यम से अध्ययन (%)	35–40 %	65–70 %

विवेचना

इस तालिका के आधार पर स्पष्ट होता है कि सामाजिक-आर्थिक स्तर का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का औसत परीक्षा परिणाम 50–60 % के बीच है, जबकि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का परिणाम 65–80 % तक पाया गया है, जो उनके बेहतर संसाधनों एवं अनुकूल वातावरण को दर्शाता है।

विद्यालय उपस्थिति के संदर्भ में भी SC वर्ग के विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम 60–70 % है, जबकि सामान्य वर्ग में यह 80–90 % तक है। इसका कारण आर्थिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ एवं संसाधनों की कमी हो सकता है।

निजी कोचिंग एवं अतिरिक्त शैक्षिक सहायता की उपलब्धता में भी बड़ा अंतर है, जहाँ SC वर्ग के केवल 30–35 % विद्यार्थी ही इसका लाभ उठा पाते हैं, जबकि सामान्य वर्ग में यह प्रतिशत 60–70 % है।

उच्च शिक्षा में नामांकन के आंकड़े भी इस असमानता को स्पष्ट करते हैं—SC वर्ग में यह 20–25 % है, जबकि सामान्य वर्ग में 45–55 % तक पहुँचता है। डिजिटल माध्यम से अध्ययन में भी स्पष्ट अंतर है, जो आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामाजिक-आर्थिक स्तर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के बीच पारिवारिक आय, माता-पिता की शैक्षिक स्थिति, आवासीय सुविधाओं तथा शैक्षिक एवं डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में विद्यमान असमानता उनके शैक्षिक प्रदर्शन में स्पष्ट अंतर उत्पन्न करती है।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थी सीमित आर्थिक संसाधनों, कम शिक्षित अभिभावकों एवं अपर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं के कारण अपेक्षाकृत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर पारिवारिक वातावरण, पर्याप्त संसाधन एवं मार्गदर्शन प्राप्त होने के कारण उनकी शैक्षिक प्रगति अधिक सुदृढ़ होती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक-आर्थिक विषमता शिक्षा में असमानता का एक प्रमुख कारण है। जब तक इन विषमताओं को कम करने के लिए प्रभावी नीतियाँ एवं योजनाएँ लागू नहीं की जातीं, तब तक शिक्षा में समान अवसर एवं समावेशन

का लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आवश्यक है कि सरकार एवं समाज मिलकर आर्थिक सहायता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता तथा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इन असमानताओं को दूर करने का प्रयास करें, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को समान शैक्षिक अवसर प्राप्त हो सके।

सन्दर्भ :

1. जनगणना भारत 2011, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5), अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई।
3. यूडीआईएसई रिपोर्ट, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
4. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. NCERT (2020), शिक्षा में समानता एवं समावेशन। नई दिल्ली।
6. NUEPA (2018), शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन पर रिपोर्ट। नई दिल्ली।
7. सिंह, आर. (2019), भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानता और शिक्षा, नई दिल्ली— एपीएच पब्लिशिंग।
8. कुमार, ए. (2021), शिक्षा और सामाजिक न्याय, पटना— बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।